बेनतीजा रही शुगर मिलों के साथ बातचीत

225 रुपये क्विंटल से ज्यादा गन्ना मूल्य नहीं दे सकते मिल ओनर

[पीटीआई *लखनऊ*]

उत्तर प्रदेश में गन्ने के बकाया भुगतान और चीनी मिलों के कामकाज को लेकर मिल मालिकों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो सका। कुछ मिल मालिकों और सरकार के बीच इन मुद्दों को लेकर हुई कई दौर की बातचीत बुधवार को आखिरकार बेनतीजा रही। राज्य सरकार ने 99 प्राइवेट शुगर मिलों के साथ लगातार दूसरे दिन लंबी बातचीत की।

इस बीच, अदालत में गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ रहे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने बैठकों के इस दौर को नाटक करार देते हुए कहा कि घाटे का रोना रो रही चीनी मिलें भारी मुनाफे में चल रही हैं और अगर वे पेराई शुरू नहीं करती हैं तो सरकार को इन मिलों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए।

शुगर इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, कुछ निजी मिल मालिकों और राज्य के चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी के बीच हुई कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। उन्होंने बताया कि इस दौरान किसानों के बकाया भुगतान को लेकर चर्चा हुई। बैठक में चीनी मिल मालिकों ने कहा कि उन पर किसानों का 2,400 करोड़ रुपया पहले ही बकाया है। मालिकों के मुताबिक, राज्य सरकार ने भले ही पेराई सीजन 2013-14 के लिए गन्ने के समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की हो, लेकिन इसके बावजूद मिलें अपना कामकाज दोबारा शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं। सूत्रों ने बताया कि शुगर मिल मालिकों का कहना है कि अब मिलें ऑपरेशन की हालत में नहीं हैं और वे 225 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा गन्ना मूल्य नहीं दे सकतीं। बैठक में चीफ सेक्रेटरी ने मिल मालिकों से पेराई शुरू करने की बात जरूर कही, लेकिन उनकी समस्याओं का ठोस समाधान नहीं निकाला जा सका।

गौरतलब है कि कोऑपरेटिव चीनी मिलों को सरकारी सब्सिडी मिलने के बावजूद 65 प्राइवेट चीनी मिलों के मालिकों ने सरकार से कहा है कि कर्ज का बोझ उतारने के लिए किसी ठोस नीति के अभाव में वे इस सीजन में मिलों में पेराई शुरू नहीं कर पाएंगे। राज्य में पेराई सीजन अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन दिवाली गुजर जाने के बाद भी गन्ने की पेराई शुरू नहीं हो सकी है।

मामले के राजनीतिक रंग पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर कुछ सरकारी चीनी मिलों में पेराई शुरू हुई है, लेकिन 99 में से 65 निजी चीनी मिलों के बंद होने से खेतों में गन्ने की फसल खड़ी है, जिससे गेहूं की बुआई में विलंब हो रहा है। किसान जगह-जगह आंदोलन कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। यहां तकरीबन 75 लाख टन चीनी का प्रोडक्शन होता है।

Economic times

28/11/13